सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–**688**
01/09/2017

मुख्यमंत्री ने श्रम संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यटन विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की

पटना, 01 अगस्त 2017 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में श्रम संसाधन विभाग एवं सहकारिता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। मुख्यमंत्री ने कल देर शाम पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की थी। समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठक के उपरांत मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह ने कल हुये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के संदर्भ में बताया कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वितीय वर्ष 2017–18 से छात्रवृति की राशि का विभाग द्वारा वितीय वर्ष 2016–17 के निर्धारित दर पर भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम के पुनर्जीवन की कार्रवाई करने एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम के साथ समन्वय स्थापित कर बिहार राज्य के सम्पूर्ण देनदारी के भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही विकास आयुक्त के स्तर पर बैठक कर निगम के पुनर्जीवन हेतु भविष्य में संचालित होने वाली योजनाओं की रूप रेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित दर एवं चयनित एजेंसी के माध्यम से प्रथम बार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिये मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना प्रारंभ की जायेगी।

श्रम संसाधन विभाग के समीक्षा के संदर्भ में मुख्य सचिव ने कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम के विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा की गयी। उन्होंने बताया कि कुशल युवा कार्यक्रम के अंदर युवाओं के क्षमतावर्द्धन के लिये उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। 360 घंटे का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। सभी चीजें ऑनलाइन होती है। इवैलुयेशन भी ऑनलाइन ही होता है। पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि कुशल युवा कार्यक्रम अन्तर्गत अब तक प्रशिक्षण के लिये 1,45,000 युवाओं का निबंधन किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने बताया कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पहले 25 हजार रूपये दिया जाता था, जिसे उनके नाम से फिक्सड कर दिया जाता था।

18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उन्हें पूरी राशि मिल जाती थी। इस योजना को जारी रखा जायेगा। इस हेतु श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु पॉच करोड़ के कॉरपस के गठन का निर्देश दिया गया। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि नियोजन प्रदान करने वाली एजेंसियों के निबंधन करने का निर्देश दिया गया है ताकि एजेंसियों के द्वारा धोखाधड़ी के मामले में उनकी पहचान हो सके एवं उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा के दौरान निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालन पर असंतोष व्यक्त किया एवं भारत सरकार को इस संबंध में प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुणवतापूर्ण चले।

सहकारिता विभाग की समीक्षा के संबंध में मुख्य सचिव ने बताया कि पैक्सों की सदस्यता को व्यापक करने के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था जल्द ही लागू की जा रही है। राज्य में पहली बार गैर–रैयत किसानों से धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था की गयी। इच्छुक किसानों को ऑनलाइन निबंधन किया गया एवं निबंधित किसानों से ही धान अधिप्राप्ति की गयी। लाभान्वितों को सहकारी बैंक के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 से भुगतान किया गया। अधिप्राप्ति के संबंध में मुख्य सचिव ने बताया कि अधिप्राप्ति के दौरान धान में नमी की मात्रा ज्यादा होने की समस्या सामने आती है। उन्होंने कहा कि पैक्सों के पास धान को सुखाने के लिये ड्रायर की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप अन्तर्गत 3049 नये गोदाम बने, जिससे 7.009 लाख मेट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित हुयी। उन्होंने बताया कि पैक्सों में गैसीफायर युक्त 356 चावल मिल बनाये गये तथा 95 चावल मिल निर्माणाधीन हैं। राज्य में बिजली की स्थिति में सुधार के दृष्टिगत 2017–18 में 120 विद्युत आधारित चावल मिल, जिनमें ड्रायर संलग्न है, शीघ्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि राज्य के सहकारी बैंकों के एन0पी0ए0 में काफी सुधार हुआ है। कुल 22 बैंकों में से 18 बैंक वर्तमान में भारतीय रिर्जव बैंक के मानकों को पूरा कर रहे हैं। सभी बैंकों में सी0बी0एस0 प्रणाली कार्यरत है। उन्होंने बताया कि पैक्सों के अंकेक्षण में काफी सुधार आया है। मुख्य सचिव ने बताया कि सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का क्रियान्वयन सुधा के तर्ज पर किया जायेगा। सब्जी उत्पादकों की त्रिस्तरीय सहकारिता समिति (प्रखण्ड/जिला/राज्य) बनायी जायेगी।

पर्यटन तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की समीक्षा के संबंध में मुख्य सचिव ने बताया कि विभाग के विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि गया के बोधगया में एक सौ करोड़ रूपये की लागत से एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जायेगा। इस कन्वेंशन सेंटर के बनने के बाद बोधगया में बड़े कार्यक्रमों को करने में सहुलियत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी सर्किटों पर विस्तृत चर्चा की गयी। कांवरिया सर्किट, गॉधी सर्किट, जैन सर्किट, बुद्ध सर्किट के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। उन्होंने बताया कि राजगीर में पर्यटकों के लिये वेणुवन तथा उससे सटे सर्किट हाउस तथा पुराना सैनिक स्कूल क्षेत्र में एक सुन्दर लैंडस्केप बनाया जायेगा।

समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, संबंधित विभागों के मंत्री– श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा/सहकारिता मंत्री श्री राणा रणधीर सिंह/पर्यटन मंत्री श्री प्रमोद कुमार/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री ब्रजकिशोर बिंद, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

****